जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार
(विधान मंडल सहित)

बजट

की

प्रमुख विशेषताएं

2024-2025

फरवरी, 2024

वित्त विभाग
बजट प्रभाग

बजट 2024-25 के मुख्य बिंदु

बजट के प्रमुख आंकड़े

प्राप्तियां:

1.	राजस्व प्राप्तियां:	97,861	करोड़ रुपए
2.	पूंजीगत प्राप्तियां:	20,867	करोड़ रुपए
	कुल प्राप्तियां	**1,18,728**	**करोड़ रुपए**

व्यय:

3.	राजस्व व्यय:	80,162	करोड़ रुपए
4.	पूंजीगत व्यय:	38,566	करोड़ रुपए
5.	**कुल व्यय**	**1,18,728**	**करोड़ रुपए**

राजकोषीय घाटा	**20,760**	**करोड़ रुपए**
जीएसडीपी के लिए पूंजीगत व्यय अंशदान:	**14.64 %**	
जीएसडीपी में अपेक्षित वृद्धि:	**7.5 %**	

वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट एक विकासोन्मुख बजट है ।

वर्ष 2024-25 का बजट जम्मू और कश्मीर के लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं और शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए संघ राज्य क्षेत्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसका तात्कालिक लक्ष्य संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में आर्थिक विकास की गति को तेज करना और इसे बहुआयामी बनाना है।

बजट 2024-25 - फोकस क्षेत्र:

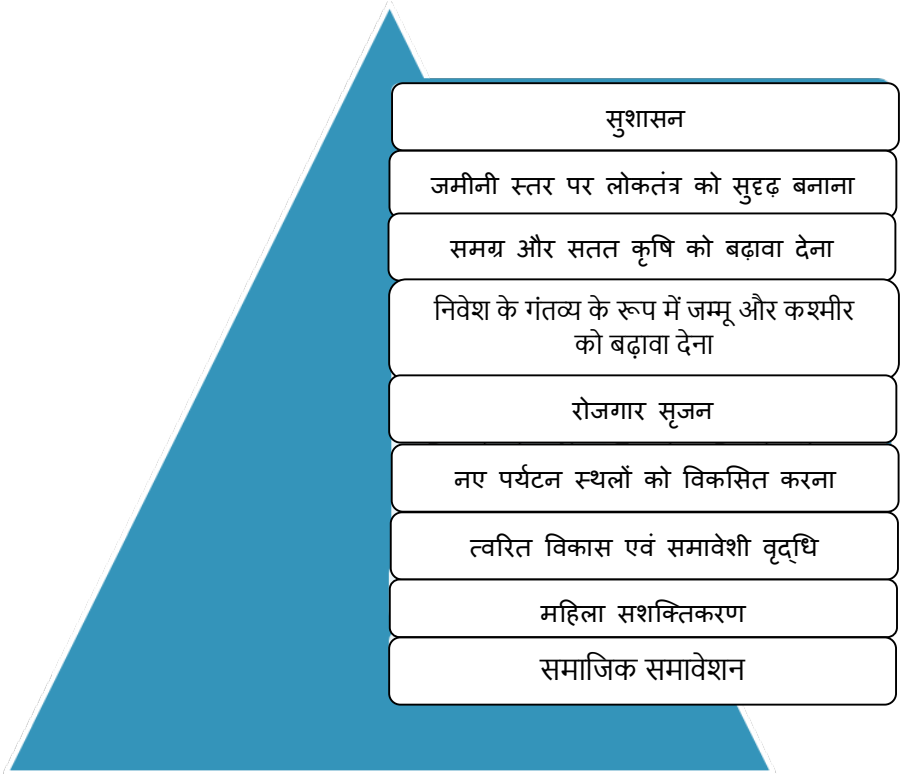

संघ राज्य क्षेत्र के संसाधन

(%प्रतिशत)

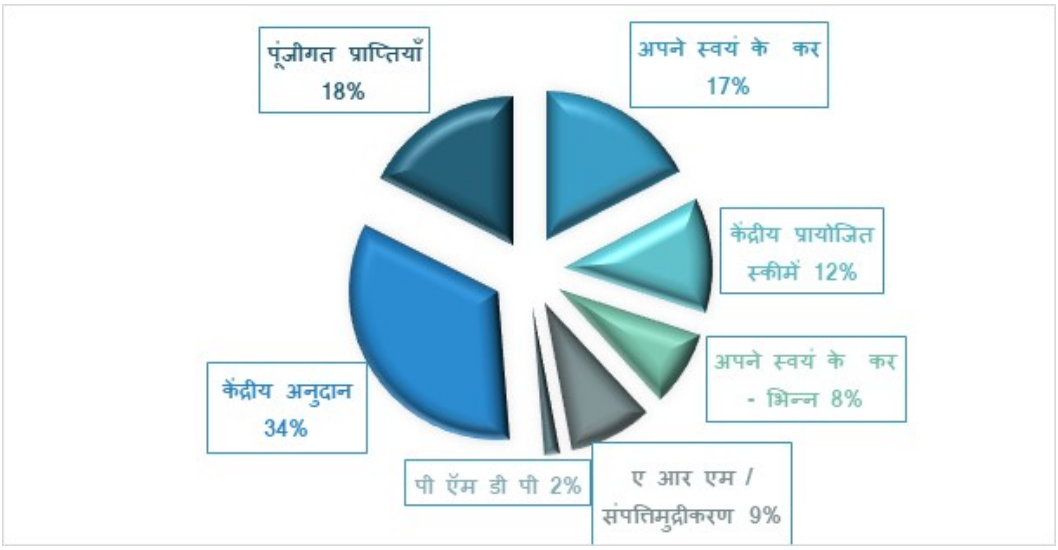

व्यय पैटर्न (%प्रतिशत)

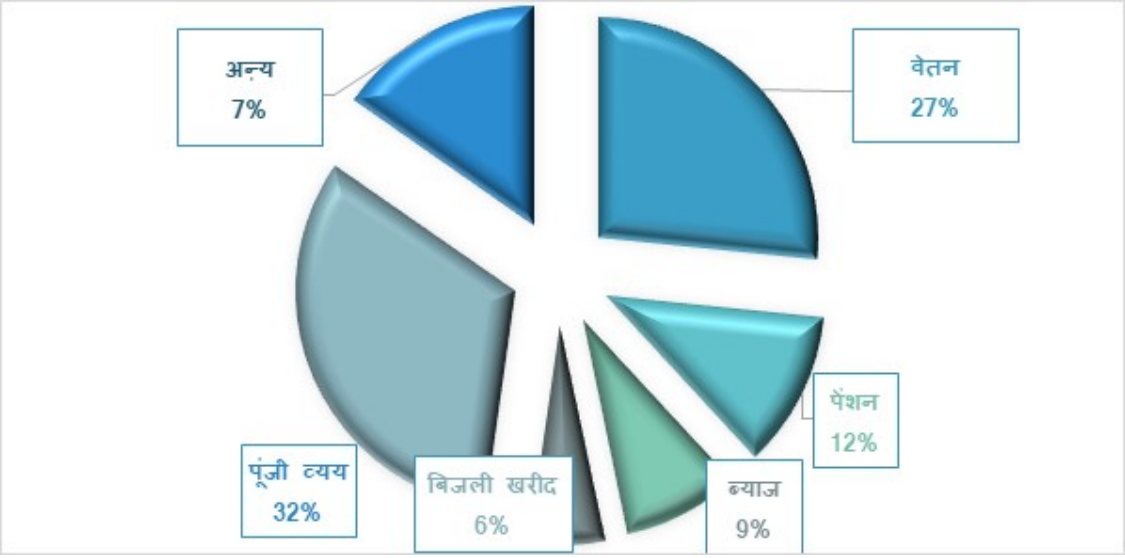

क्षेत्रीय आवंटन

राजस्व व्यय		पूंजीगत व्यय
Rs.12,580.36 करोड़ रुपए	प्रशासनिक क्षेत्र	*Rs.1,361.70* करोड़ रुपए
Rs. 24,599.64 करोड़ रुपए	सामाजिक क्षेत्र	*Rs. 3,779.02* करोड़ रुपए
5,306.31 करोड़ रुपए	आर्थिक क्षेत्र	*6,853.55* करोड़ रुपए
12,675.35 करोड़ रुपए	बुनियादी ढांचा क्षेत्र	*13,511.66* करोड़ रुपए

ई-गवर्नेंस की पहलें

1. सभी कार्यालयों और पंचायतों में ई-ऑफिस को अपनाया जाएगा।

2. जम्मू और श्रीनगर में फिजिकल सत्यापन इकाइयां स्थापित की जाएंगी।

3. वित्त विभाग में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) और व्यवहार्यता अंतर निधि (वीजीएफ) सेल को नया रूप प्रदान किया जाएगा।

4. पीएम गति शक्ति को पूरी तरह लागू किया जाएगा।

5. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नागरिकों को सेवाओं की प्रभावी डिलीवरी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), मशीन लर्निंग (एमएल) और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों को लागू किया जाएगा।

विभिन्न विभागों/क्षेत्रों की प्रमुख विशेषताएं

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र

- कृषक समुदाय को उनके घर पर सुविधाएं प्रदान करने के लिए 2000 किसान खिदमत घरों (केकेजी) की स्थापना करना।
- विभागीय डिपार्टमेंटल सीड मल्टीप्लिकेशन फार्मों का सुदृढ़ीकरण।

- जम्मू और कश्मीर में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता सुधार परियोजना (जेकेसीआईपी) को कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय निधि (आईएफएडी) से 100 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण के अनुमानित मूल्य के साथ लागू किया जाएगा। परियोजना का लक्ष्य कृषि संबंधी कार्यों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करके, ग्रामीण परिवारों की आय में निरंतर वृद्धि में योगदान देना है।
- 1000 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए सुनिश्चित सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए 283 बोरवेल का निर्माण किया जाएगा और 520 सिंचाई पंप सेट वितरित किए जाएंगे।
- लगभग 12000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करने के साथ 4500 डेयरी इकाइयां और 3000 भेड़ पालन इकाइयां स्थापित की जाएंगी।
- पांच वर्षों की अवधि में दूध उत्पादन में 25 से 45 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि और दूध संग्रह/चिलिंग में 2.0 से 8.5 लाख लीटर प्रति दिन (एलएलपीडी) की वृद्धि।
- तकनीकी सहयोग से मछली उत्पादन को 30670 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 35250 मीट्रिक टन किया जाएगा।

- उच्च घनत्व वृक्षारोपण को बढ़ावा देने और बागानों को नया रूप प्रदान करने के लिए डिजाइनर पौधों का उत्पादन।
- फलों के मूल्य संवर्धन, कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 50 फ्रूट का ड्राई फ्रूट सहित प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जाएंगी।
- अगले वित्त वर्ष के दौरान 83000 मीट्रिक टन नियंत्रित वातावरण (सीए) भंडारण क्षमता शामिल की जाएगी।

स्वास्थ्य और देखभाल

- वर्ष 2024-25 के दौरान जम्मू और श्रीनगर में दो कैंसर संस्थान पूरी तरह से चालू हो जाएंगे।
- डीएनबी सीटों को 400 तक बढ़ाना, जिससे विशेषज्ञों की उपलब्धता में सुधार होगा।
- 1.35 करोड़ आबादी के लिए एबीएचए आईडी बनाकर स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा।
- उच्च रक्तचाप और मधुमेह के लिए 30+ आयु वर्ग की 100% जांच।
- 16 मौजूदा सुविधाओं और 10 नई स्वास्थ्य सुविधाओं में डायलिसिस सेवाओं को और सुदृढ़ बनाया जाएगा।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत 400 लाख श्रम दिवस सृजित किये जायेंगे।
- हिमायत योजना के तहत करीब 7000 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण पूरा किया जाएगा।

- एनआरएलएम के तहत वर्ष 2024-25 के दौरान 12000 अतिरिक्त स्वयं सेवी समूह (एसएचजी) बनाए जाएंगे।
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत 100% इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ 600 नए पंचायत घरों का निर्माण किया जाएगा।
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत पंचायती राज संस्थान (पीआरआई) के सदस्यों को 2.60 लाख श्रम दिवस का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाय-जी) के तहत 80,000 घरों का निर्माण किया जाएगा।
- स्वच्छ/कूड़ा और प्लास्टिक मुक्त बनने के लिए गांवों में ठोस/तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए।
- वर्ष 2024-25 के दौरान एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के तहत 1800 निर्माण कार्यों को पूरा करने के साथ 26000 हेक्टेयर क्षेत्र को शोधित किया जाएगा।

विद्युत् क्षेत्र

- गुरेज़ में तुलैल घाटी तक ऊर्जा आपूर्ति/ग्रिड कनेक्टिविटी का विस्तार।
- 220/132 केवी स्तर पर 02 नए ग्रिड सब-स्टेशनों का निर्माण, जो रेडमपोरा (160 एमवीए) और रथसन बीरवाह (100 एमवीए) में 260 एमवीए की क्षमता का संवर्धन करेगा।
- 03 नई ट्रांसमिशन लाइनों, 132 केवी स्तर पंपोर-नाउबुग-चादूरा, 132 केवी स्तर बांदीपोरा-गुरेज़ और 80 एमवीए ग्रिड सब-स्टेशन डूसू-रफियाबाद के लिए 132 केवी डायरेक्ट सर्किट टैप लाइन का निर्माण ।
- वोल्टेज में सुधार और फॉल्ट लेवल में कमी के लिए अत्यंत ओवरलोडेड अतिभारित 11 केवी फीडरों को अलग करना।

पर्यटन एवं संस्कृति

- 20 ऑफ-बीट पर्यटन स्थलों, 10 जम्मू और 10 कश्मीर संभागों के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं का विकास।
- केरन का सीमावर्ती पर्यटक ग्राम के रूप में विकास।
- तोसामैदान और सीतारण सर्किट का विकास।
- "मॉक विलेज" के रूप में पारंपरिक व्यवस्था के साथ सांबा में डुग्गर दानी का विकास।
- पटनीटॉप में 130 मीटर (425 फीट) ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ का निर्माण और स्थापना।
- जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के भीतर प्रमुख स्थलों पर ध्यान केंद्रित करने और उन पर जोर देने के लिए लखनपुर में भव्य स्वागत/प्रवेश द्वार का निर्माण।
- 75 चिन्हित विरासत स्थलों/सांस्कृतिक स्थलों के पुनरुद्धार और जीर्णोद्धार संबंधी कार्य को पूरा करना।
- 8 सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन।
- श्रीनगर में अत्याधुनिक सुफियाना स्कूल के संचालन सहित, संरचित कार्यक्रमों के माध्यम से जम्मू और कश्मीर में सूफीवाद का प्रचार और प्रसार करना।
- सभी पुस्तकालयों का डिजिटलीकरण करना।

जल आपूर्ति एवं सिंचाई

- जम्मू-कश्मीर के सभी 18.36 लाख घरों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन होंगे।
- शेष 4000 गांवों का हर घर जल (एचजीजे) प्रमाणीकरण।

- 3244 जेजेएम योजनाओं को उनके संचालन और रखरखाव के लिए पानी समितियों/पीआरआई को सौंपा जाएगा।
- 78 प्रमुख मध्यम सिंचाई योजनाएं पूरी की जाएंगी और 250 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन/स्थायीकरण किया जाएगा।
- 2400 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित करने के लिए 297 लघु सिंचाई योजनाएं पूरी की जाएंगी, जिससे 4400 लोगों की आबादी लाभान्वित होगी।
- 302 बाढ़ नियंत्रण योजनाएं पूरी की जाएंगी और 3000 हेक्टेयर भूमि को पुनः प्राप्त और संरक्षित किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-हर खेत को पानी (पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी) के तहत वर्ष 2024-25 के दौरान 51 योजनाएं पूरी की जाएंगी और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ऋण सहायता के तहत 12 योजनाएं पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।
- शाहपुर कंडी बांध के वर्ष 2024-25 के दौरान चालू होने की संभावना है, जिससे जम्मू-कश्मीर को कठुआ और सांबा में 32173 हेक्टेयर भूमि के लिए 1150 क्यूसेक सिंचाई जल सुविधा का लाभ मिलेगा।

आवास एवं शहरी विकास

- 65.33 एमएलडी क्षमता के सीवरेज शोधन वाले 05 सीवरेज शोधन संयंत्र (एसटीपी) कार्यान्वयन के अधीन हैं।
- अमृत 2.0 के तहत, 78 यूएलबीएस की 153 परियोजनाओं के लिए यूटी जल कार्य योजना पूरी हो चुकी है। इसमें जल आपूर्ति कनेक्शन के लिए 99 परियोजनाएं शामिल हैं, जिनका लक्ष्य 2.25 लाख नए नल घरेलू कनेक्शन प्रदान करना है।
- स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 262 परियोजनाओं में से 207 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 55 परियोजनाओं का वर्ष 2024-25 में पूरी होने की संभावना है।
- पुराने शहर में अवरोधन और डायवर्जन नेटवर्क बिछाकर तवी नदी का प्रदूषण कम करना।
- ट्रांसपोर्ट नगर नरवाल जम्मू और परिमपोरा श्रीनगर का पुनर्निर्माण करना।

शिक्षा

- समग्र शिक्षा अभियान के तहत पुस्तकों की खरीद के लिए प्राथमिक से वरिष्ठ माध्यमिक तक के स्कूलों को कवर करने के लिए ₹5,000 से ₹20,000 तक का अलग से वार्षिक पुस्तकालय अनुदान देना।

- 2000 किंडरगार्टन स्थापित किये जायेंगे।
- छात्रों के पोषण संबंधी स्वास्थ्य में सुधार के लिए मध्याह्न भोजन योजना के तहत प्रारंभिक स्तर (I से VIII) के लगभग 8.43 लाख छात्रों को केवल फोर्टिफाइड चावल परोसा जाएगा।
- प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम एसएचआरआई) योजना के तहत 233 स्कूलों की अवसंरचना को उन्नत किया जाएगा।
- न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम (एनआईएलपी) के तहत 3.50 लाख वयस्कों को साक्षर बनाया जाएगा।
- बीपीएल छात्राओं के लिए बेटी अनमोल योजना के तहत ₹5000/प्रति छात्र की दर से छात्रवृत्ति।
- 18723 स्कूलों को ₹18.50 करोड़ की वित्तीय लागत से खेल उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।
- वर्ष 2024-25 के दौरान 05 नव स्थापित कॉलेजों का निर्माण पूरा किया जाएगा।
- दो छात्रावास ब्लॉक, दो विज्ञान ब्लॉक और 06 अतिरिक्त व्याख्यान ब्लॉकों का विभिन्न कॉलेजों में निर्माण कार्य पूरा किया जाना है।
- वर्ष 2024-25 में 08 कॉलेजों को आकलन किया जाएगा और मान्यता दी जाएगी।

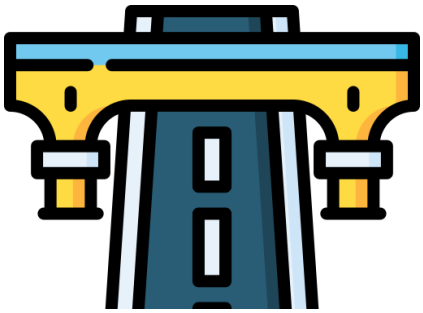

कनेक्टिविटी

वर्ष 2024-25 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)/शहर और कस्बों संबंधी योजना/केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ)/राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ऋण सहायता/गड्ढा मुक्त सड़क योजना के तहत 4000 किलोमीटर लंबी सड़क पर कोलतार बिछाया जाएगा।

औद्योगिक विकास

- विकास के लिए 46 नए औद्योगिक एस्टेट की पहचान की गई है जो निवेश को आमांत्रित करेंगे और रोजगार के अवसर पैदा करेंगे
- वर्ष 2024-25 के दौरान जम्मू और कश्मीर ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (जेएंडके आरईजीपी) के तहत, 1167 इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।
- स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए नई नीति लाई जाएगी।
- मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों में अवसंरचना का उन्नयन।
- निजी औद्योगिक संपदा विकास नीति को नया रूप दिया जाएगा।

सामाजिक/जनजातीय कल्याण

- सभी बौद्धिक चुनौती व्यक्तियों को निर्मया स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कवर किया जाएगा।
- वात्सल्य सदन जम्मू को चालू किया जाएगा।
- चरणबद्ध रूप से 1000 आंगनवाड़ी केंद्रों को आकर्षक और रोचक बनाया जाएगा।
- जनजातीय आबादी को 250 छोटे प्रकार के ट्रैक्टर और लिंक रोड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।
- अनुसूचित जनजाति बस्तियों को 70 हैंडपंप उपलब्ध कराए जाएंगे।
- प्रवासी जनजातीय आबादी को स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराएं जाएंगे।
- ट्रांस-ह्यूमन जनजातीय आबादी के लिए ट्रांजिट आवास स्थापित किए जाएंगे जिसमें 150-200 परिवारों के लिए आवास, सामुदायिक रसोई, चिकित्सा औषधालय, पशु चिकित्सालय, सामुदायिक शौचालय और पशुधन यार्ड शामिल हैं।

- "प्रधानमंत्री आदि ग्राम आदर्श योजना (पीएमएएजीवाई)" योजना के तहत 500 अनुसूचित जनजाति आबादी वाले 186 गांवों को कवर किया जाएगा।
- वर्ष 2024-25 के दौरान 10 दुग्ध गांवों को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

कश्मीरी प्रवासियों को राहत और पुनर्वास

- वर्ष 2024-25 के दौरान कश्मीरी प्रवासी कर्मचारियों के लिए ट्रांजिट आवास के रूप में 1500 फ्लैटों का निर्माण पूरा करना।
- वर्ष 2024-25 में कश्मीरी प्रवासियों के लिए पीएम-पैकेज के तहत 6000 पदों में से शेष 350 पद भरे जाएंगे।

युवा सशक्तिकरण और युवाओं हेतु रोजगार

- स्व-रोजगार उद्यम शुरू करने के लिए युवाओं को सीड कैपिटल फंड योजना, युवा स्टार्ट-अप ऋण योजना, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम योजना, महिला उद्यमिता कार्यक्रम और मिशन युवा योजनाओं के तहत स्व-रोजगार योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- मॉडल कैरियर सेंटर (एमसीसी) के माध्यम से इच्छुक नौकरी चाहने वालों के लिए आउटरीच और परामर्श संबंधी कार्यकलाप आयोजित किए जाएंगे।

खेल एवं युवाओं हेतु पहलें

- वर्ष 2024-25 के दौरान पंचायत, ब्लॉक, जिला, संघ राज्य क्षेत्र और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले विभिन्न खेल आयोजनों में 75 लाख युवाओं की भागीदारी।

- वर्ष 2024-25 में 20 राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।
- 200 खेल मैदान और 100 खेल कोर्ट बनाए जाएंगे।
- मौलाना आज़ाद स्टेडियम, जम्मू और गिंडुन पार्क राजबाग, श्रीनगर में स्विमिंग पूल का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा।

कौशल विकास

- 10 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे।
- बड़े व्यापारिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के सहयोग से 1000 उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित की जाएगी।
- एनआरएलएम के साथ पंजीकृत 6000 महिला स्वयं सहायता समूहों का प्रशिक्षण पूरा किया जाना है।

वानिकी एवं पर्यावरण

- पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने, मिट्टी के कटाव को रोकने और जैव विविधता का संवर्धन करने के उद्देश्य से 190 लाख देशी पेड़ों का रोपण और कम लागत वाले 100 लाख हरित वृक्षों संबंधी पहलों ।
- जम्मू-कश्मीर के सभी शहरी स्थानीय निकायों में कम से कम एक नगर वैन, नगर वाटिका या एक इको पार्क ।
- जंगलों के बाहर पेड़ों की संख्या में वृद्धि करने और आजीविका में सुधार के लिए स्थानीय, औषधीय और प्रजातियों महत्त्व वाले 10 लाख पौधे किसानों के बीच वितरित किए जाएंगे।
- इको-पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए घराना, होकरसर और शालबुघ जैसी आर्द्रभूमियों में अवसंरचना का विकास किया जाएगा।
- जम्मू में सतत परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन (सीएएक्यूएमएस) की स्थापना।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

- प्रधान मंत्री खाद्य अनुपूरक योजना के तहत प्राथमिकता वाले परिवारों को प्रति माह सब्सिडी दरों पर अतिरिक्त 10 किलो चावल प्रदान किए जाएंगे।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सभी लाभार्थियों का ई-केवाईसी पूरा किया जाना है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

- पीएम-कुसुम घटक "सी" के तहत चरणबद्ध रूप से 4000 ए सी कृषि पंपों को सौर पंपों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- सरकारी भवनों पर लगभग 04 मेगावाट के रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाये जायेंगे।
- पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से श्रीनगर की डल झील में 100 किलोवाट का फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र संस्थापित किया जाएगा।
- घरेलू वायु प्रदूषण और ईंधन के उपयोग को कम करने के लिए जनजातीय क्षेत्रों में 5000 उन्नत बायोमास कुक-स्टोव उपलब्ध कराए जाएंगे।
- सौर पार्कों के विकास के लिए भूमि बैंक की पहचान की जाएगी।
- विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएडीपी) के तहत पर्यटन और धार्मिक स्थलों को पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से सुसज्जित करने के लिए कार्य किया जाएगा।

सुरक्षा संबंधी गतिविधियाँ

- घुसपैठ रोधी ग्रिड को सुदृढ़ बनाने के लिए 42 नई सीमा पुलिस चौकियों का निर्माण।
- सार्वजनिक स्थानों पर कमांड-एंड-कंट्रोल सेंटर के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाना पूरा किया जायेगा ।
- पुलिस स्टेशनों/पुलिस चौकियों एवं पुलिस आवास परिसरों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार।
- 1218 सामुदायिक/पृथक व्यक्तिगत बंकरों का निर्माण किया जाएगा।
- इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) परियोजना का कार्यान्वयन।

प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटन

क्र.सं.	योजनाएं/कार्यकलाप	आवंटन 2024-25 (करोड़ रुपये में)	पहलें
1	समग्र कृषि विकास कार्यक्रम (एचएडीपी)	934	अगले पांच वर्षों की अवधि में 5013 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 29 परियोजनाओं के लिए समग्र कृषि विकास कार्यक्रम।
2	बागवानी	60	कोल्ड स्टोरेज एवं उच्च घनत्व वृक्षारोपण को संस्थापित करना।
3	औद्योगिक एस्टेट	400	निवेश एवं रोजगार सृजन हेतु नये औद्योगिक संपदाओं का विकास।
4	औद्योगिक प्रोत्साहन	40	औद्योगिक नीति और स्टार्ट अप संबंधी के प्रावधानों के अनुसार प्रोत्साहन देना।
5	जीएसटी रिफंड	450	औद्योगिक इकाइयों के लिए प्रोत्साहन के रूप में जीएसटी रिफंड
6	व्यापार संवर्धन	15	जम्मू और कश्मीर व्यापार संवर्धन संगठन के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रमों के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा देना।
7	रोजगार योजनाएँ	200	युवाओं के स्वरोजगार के लिए युवा स्टार्ट-अप/सीड कैपिटल फंड योजनाएं और मिशन युवा योजनाओं का कार्यान्वयन
8	बैंकों का पूंजीकरण	500	जम्मू-कश्मीर बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और सहकारी बैंकों के लिए पूंजीगत समर्थन।
9	सड़क क्षेत्र	3983	पीएमजीएसवाई, सीआरआईएफ एवं नाबार्ड ऋण योजना के तहत सड़कों का निर्माण।
10	नई जल विद्युत परियोजनाओं के लिए इक्विटी	660	रैटल, कावर और किरू जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए इक्विटी सहयोग।
11	जल जीवन मिशन	3491	सभी घरों में चालित नल कनेक्शन।
12	बाढ़ प्रबंधन	390	झेलम नदी की बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं के लिए।
13	स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)	370	सभी शहरी स्थानीय निकायों में ओडीएफ+ का दर्जा प्राप्त करना।
14	सीवरेज प्रबंधन	100	सीवरेज शोधन संयंत्रों प्लांट का निर्माण।

क्र.सं.	योजनाएं/कार्यकलाप	आवंटन 2024-25 (करोड़ रुपये में)	पहलें
15	नई टाउनशिप	70	आवास हेतु नये टाउनशिप का विकास।
16	डल विकास	50	डल झील का विकास एवं संरक्षण।
17	सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ	1430	लाडली बेटी एवं विवाह सहायता योजना के अंतर्गत वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन की सहायता।
18	जनजातीय कल्याण	70	आदिवासियों के कल्याण के लिए अवसंरचना जैसे आदिवासी छात्रावास, दूध गांव, खानाबदोश आश्रय और पुस्तकालय।
19	कश्मीरी प्रवासियों को राहत और पुनर्वास	400	पीएम पैकेज के तहत नियुक्त कश्मीरी प्रवासी कर्मचारियों के लिए आवास का निर्माण।
20	समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए)	1907	एसएसए कर्मचारियों के लिए आवर्ती व्यय और प्राथमिक और माध्यमिक संस्थानों की अवसंरचना के लिए गैर-आवर्ती व्यय।
21	पीएम श्री	175	गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पीएम श्री स्कूलों की स्थापना।
22	गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा	30	अवसंरचना और कैरियर परामर्श के संबंध में स्कूलों में गुणवत्ता में सुधार करना।
23	उच्च शिक्षा	400	कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की अवसंरचना के लिए।
24	औषधियाँ एवं उपकरण	500	स्वास्थ्य संस्थानों के लिए दवाएँ, मशीनरी और उपकरण उपलब्ध कराना।
25	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम)	1271	एनएचएम कर्मचारियों के लिए आवर्ती व्यय और स्वास्थ्य संस्थानों की अवसंरचना के लिए गैर-आवर्ती व्यय
26	प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)	1093	ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीन गरीब परिवारों को अपना घर बनाने हेतु सहायता
27	पीआरआई और यूएलबी अनुदान	1313	पीआरआई और यूएलबी के विकास कार्यों के लिए।
28	डीडीसी/बीडीसी अनुदान	271.25	विकास निधि के रूप में 20 डीडीसी के लिए प्रत्येक 10 करोड़ रुपये की दर से 200 करोड़ रुपये और 285 बीडीसी के लिए 25 लाख रुपये की दर से 71.25 करोड़ रुपये होंगे।

क्र.सं.	योजनाएं/कार्यकलाप	आवंटन 2024-25 (करोड़ रुपये में)	पहलें
29	स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षा और आवास	80	डीडीसी/बीडीसी/पीआरआई सदस्यों के लिए आवास और कार्यालयों की सुरक्षा और निर्माण।
30	पर्यटन क्षेत्र	123	पर्यटन को बढ़ावा देना, नए पर्यटन स्थलों का विकास, नए सर्किट, रोपवे और गोल्फ को बढ़ावा देना।
31	संस्कृति का संरक्षण	115	विरासत का संरक्षण, त्योहारों और सिनेमा/थिएटर को बढ़ावा देना।
32	विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	100	झेलम तवी बाढ़ रिकवरी परियोजना (जेटीएफआरपी) के तहत अवसंरचना का निर्माण।
33	खेल पहलें	140	खेल सुविधाओं का निर्माण।
34	नवीकरणीय ऊर्जा	150	सौर छतों और सौर पंपों की संस्थापना
35	सुरक्षा संबंधी अवसंरचना	65	सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस हाउसिंग कॉलोनीज, बंकरों का निर्माण और पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी की स्थापना।

*****